

2



ग्रामवासियों ने एसडीएम को जापान सौंपा

3



छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन

5



अग्निनेत्री से लोकसभा सांसद तक का सफ़र

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 22

प्रति सोमवार, 7 अक्टूबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है राज्य को नक्सल समस्या मुक्त बनाने का संकल्प

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

किसी भी राज्य में खुशहाली और समृद्धि तब तक संभव नहीं है जब तक वहां भय मुक्ति का वातावरण न बनाया जाये। फिर वह भय भले ही नक्सलियों का क्यों न हो। छत्तीसगढ़ में वर्षों से नक्सलियों ने राज्य की जनता का सुख-चैन छीना है। ऐसे में राज्य की जनता को सुकून और खुशहाली देने के लिये प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल मुक्त राज्य बनाने का पहला तो संकल्प लिया और उसके बाद लगातार राज्य को सिलसिलेवार ढंग से चलाये जा रहे योजनाबद्ध अभियानों से नक्सलियों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। नक्सलियों के आतंक की समाप्ति



सफल हो रहे साय सरकार के प्रयास

का यह अभियान अभी से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा चुनाव के पहले से शुरू कर दिया था। उन्हीं के नेतृत्व में राज्य में नक्सलियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सरकार ने यह साबित भी किया है। यह संकल्प ऐसे समय में और भी महत्व रखता है, जब सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने को लेकर गंभीर है।

दशकों से बड़ी समस्या है नक्सलवाद

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद दशकों से एक बड़ी समस्या रही है। नक्सली राज्य के विकास में बाधक बनते रहे हैं। कई बड़े नक्सलियों ने हाल के दिनों में आत्मसमर्पण किया है, वहीं कई मारे गए या गिरफ्तार हुए। हालांकि अभी भी नक्सली रह-रह कर सिर उठाते रहते हैं। इसलिए नक्सली समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने तक इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। राज्य के विकास के लिए उद्योगीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है। उद्योगपतियों को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि उन्हें यहां भयमुक्त वातावरण मिलेगा। (शेष पेज 7 पर)

मध्यप्रदेश में खाकी वर्दी वाले संरक्षक बनते जा रहे भक्षक शिक्षकों का सम्मान करने के बजाय बरसा रहे लाठियां, गोलियां दागने की दी धमकी

शिक्षकों का सम्मान करने के बजाय बरसा रहे लाठियां, गोलियां दागने की दी धमकी

-विजया पाठक

स्कूल की पाठशाला में बच्चों को जीवन का क...ख...ग...घ... और संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक आज बुरी तरह से अपमानित होने को मजबूर हैं। इन शिक्षकों की बात तो मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षामंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने तो पहले ही सुनने से इंकार कर दिया था वहीं, अब शिक्षकों की परेशानियों को दूर करने के बजाय मध्यप्रदेश सरकार इन शिक्षकों पर लाठियों बरसाने को आतुर है। लगातार इन शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, इन पर



क्रूरतम ढंग से लाठियां-डंडे बरसाये जा रहे हैं। यही नहीं शासन की हिमाकत तो तब शर्मसार हो गई जब

पुलिस ने इन शिक्षकों की जान पर हमला करते हुए सीधे गोलियां चलाने के आदेश दे दिये। राज्य में शिक्षक और विद्वानों के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है और प्रदेश के मुखिया सहित पूरा शासन-प्रशासन आंख में पट्टी बांधे बैठा हुआ है। शिक्षक न सिर्फ एक व्यक्ति होता है, बल्कि वह अपने आप में पूरा विद्यालय है जो बच्चों को संस्कार बनाता है, जीवन की जीने के सलीके देता है और अच्छे-बुरे में भेदभाव के अंतर को बतलाता है। ऐसे में शिक्षकों के साथ हो रहा यह अनाचार सच में मध्यप्रदेश की संस्कृति को शर्मसार कर देने वाला है। (शेष पेज 7 पर)

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के एक बचकाने कदम ने कांग्रेस पार्टी की एकता और विश्वसनीयता से उठाया पर्दा



बगैर प्रदेश अध्यक्ष को सूचित किए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा विधायकों का एक समूह, आलाकमान नाराज

-विजया पाठक

पिछले दिनों मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी आलाकमान के बुलावे पर गुप्त ढंग से दिल्ली मुलाकात करने पहुंचे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भले ही पार्टी आलाकमान को यह कहकर संतुष्ट कर दिया हो कि पार्टी में सब कुछ अच्छा चल रहा है और पार्टी के नेता एकजुट हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अभी तक कांग्रेस नेताओं के आपसी मतभेद और मनभेद की जो खबरें आ रही थीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के एक बचकाने कदम ने इस पूरे मामले के ऊपर से पर्दा उठा दिया। उमंग सिंगार कांग्रेस के कुछ विधायकों को साथ लेकर दो दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे। बैठक में मोहन यादव से कांग्रेस विधायक से अपने क्षेत्रों में विकास के कार्यों के बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष बगैर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को सूचित किए विधायकों से साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। (शेष पेज 7 पर)

ग्रामवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा



-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिगरजी। तहसील के ग्राम छिदगांव मेल एवं पिपलिया कला के ग्रामवासियों द्वारा टिगरजी एसडीएम को ज्ञापन दिया जाकर अवगत कराया गया। ग्राम छिदगांव मेल में एसएमएस बायो फ्यूल कंपनी को बंद किया जाए इस बात को लेकर कई बार आवेदन निवेदन किए जाने के पश्चात ग्रामवासियों की सुनवाई नहीं होने के कारण ग्रामवासी इस कंपनी को बंद करवाने हेतु अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। इस बात की सूचना एसडीएम को दी गई। ग्रामवासियों ने

ज्ञापन में बताया एसएमएस कंपनी से निकलने वाली दुर्गंध एवं उसमें एकत्रित एवं निर्मित किए जाने वाले जलनशील पदार्थ के कारण ग्रामवासियों का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण गहरे संकट में फंस गया है तथा इसमें ग्रामीण काफी परेशान हैं। ग्रामवासियों को स्वास्थ्य एवं हृदय में संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी समस्याओं से परेशान है। त्रस्त होकर ग्रामवासी ने कोई सुनवाई न होने के कारण शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करने का निश्चय किया है।



सेन्ट्रल जोनल राउंड में एम्स भोपाल की टीम विजयी

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. गोंडाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के नेतृत्व में एम्स भोपाल की टीम ने भारतीय बाल नेफ्रोलॉजी सम्मेलन (ISPNCON) 2024 में केंद्रीय क्षेत्र के जोनल राउंड में जीत हासिल की है। यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता प्रयागराज में 4 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गयी थी। एम्स भोपाल से बाल रोग विभाग

की द्वितीय और तृतीय वर्ष की जुनियर रेजिडेंट डॉ. सोनल राजमाने और डॉ. पूजा फुलिंगिस्कर ने भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। राष्ट्रीय स्तर का फाइनल राउंड 7 दिसंबर 2024 को दिल्ली में आयोजित होगा, जहां एम्स भोपाल की टीम देश के अन्य हिस्सों से आए चिकित्सकों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "यह जीत हमारे रेजिडेंट्स की

मेहनत और समर्पण का फल है और मुझे पूरा विश्वास है कि एम्स भोपाल की टीम राष्ट्रीय राउंड में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को जारी रखेगी।" बाल रोग विभाग की प्रमुख प्रो. शिखा मलिक ने भी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, "डॉ. अजय सिंह के मार्गदर्शन में हमारी टीम ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की है। यह जीत सभी की मेहनत और लगन का प्रतीक है। मैं उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ कि वे आगे भी इसी तरह मेहनत करें।"



स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आरटीओ ने श्रमदान कर मनाई गांधी जयंती

-नरेन्द्र वीक्षित

जगत प्रवाह. गर्गापुरम। कलेक्टर के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आरटीओ अधिकारी निशा चौहान ने आरटीओ कार्यालय में समस्त स्टाफ के साथ मिलकर कार्यालय परिसर तथा बगीचे में साफ सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया

तथा इसे हर वर्ग तथा समाज के लिए जरूरी बताया, स्वच्छता से ही कई प्रकार की बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है और शुद्ध वातावरण से अपनी आयु को बढ़ाया जा सकता है। आरटीओ अधिकारी द्वारा सफाई के बाद देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करके पुष्प अर्पित किए। इसके बाद आरटीओ ने सफाई मित्र बंटो टांक

को "बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ" का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आरटीओ अधिकारी ने अपने समस्त स्टाफ को कार्यालय, अपने घर के आस पास तथा प्रत्येक जगह सफाई रखने को शपथ दिलाते हुए अपने जीवन में अपनाते और दूसरों को प्रेरित करने के लिए कहा।

ओवर एज और चार साल पूरी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके अमले को मिल रहे डबल प्रभार

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले में सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान की गतिविधियां राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों के विपरीत संचालित होने के कारण पटरी से उतर चुकी है जिसका एकमात्र कारण जिला शिक्षा केंद्र नरसिंहपुर कार्यालय की भ्रष्टाचार से सराबोर और विभागीय नीति नियमों से विपरीत कार्य शैली प्रतीत हो रही है। जिले के संपूर्ण शिक्षा जगत में यह चर्चा विद्यमान हो रही है कि डीपीसी नरसिंहपुर डॉ. आरपी चतुर्वेदी उनके कृपा पात्र प्रभार संभाल रहे एपीसी और सभी ब्लॉकों में बैठे बीआरसी और प्रभारी बीआरसी बीएसी जनशिक्षक प्रतिनियुक्ति मामला बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति मापदंडों के अनुसार आयु सीमा पार कर चुका है और कई शिक्षक गलत विषयों से प्रतिनियुक्ति पर बने होने के बावजूद अपनी प्रतिनियुक्ति की पूरी कालावधि भी पूर्ण कर चुकने के बाद वापस अपनी मूल शालाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने जाने से गुरेज कर रहे हैं।

साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी अनिल व्योहार अपने शिक्षकों को

प्रतिनियुक्ति पूर्ण होने के बाद भी बुलाने में असमर्थ और नाकारा सिद्ध हुए हैं ऐसी स्थिति के बावजूद भी जबकि नरसिंहपुर जिला स्कूल शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का गृह जिला है मगर मंत्री का खौफ कहीं भी जिले के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों में नजर नहीं आ रहा है मंत्री की छवि और साख को धूमिल करने में वह कतई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

जिन प्रतिनियुक्ति पूर्ण कर चुके अमले को हटाना चाहिए या जो उच्च पद प्रभार या ट्रांसफर और अन्य कारणों से सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों से वापस हो जाने चाहिए ऐसे अमले को डीपीसी नरसिंहपुर कार्यालय और बीआरसी कार्यालय द्वारा बड़ी संख्या में डबल प्रभार देकर भ्रष्टाचार और गलत मापदंडों भरी कार्य शैली से काम करते हुए भारी और रिकॉर्ड तोड़ गफलत भरे करतब अंजाम दिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके जनशिक्षक प्रतिनियुक्ति पूरी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने वाले अमले को हटाने की मांग तेज हो गई है। (जगत फीचर्स)



छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल-ऑपरेशन, 2 घंटे में 31 नक्सली ढेर

-संवाददाता

उग्रत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में सिक्वॉरिटी फोर्स ने शुक्रवार को 31 नक्सलियों को मार गिराया है, यह ऑपरेशन बस्तर इलाके में चलाया गया था और 24 साल पहले राज्य के गठन के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यह घटना कोंकण जिले में सुरक्षा बलों के जरिए 29 नक्सलियों को मार गिराने के ठीक 5 महीने बाद हुई है। पुलिस महानिरीक्षक (बस्तर रेंज) सुंदरराज पी ने बताया कि नारायणपुर-दंतेवाड़ा सीमा पर थुलथुली और नेंदुर गांवों के बीच जंगल में दोपहर

एक बजे हुई इस मुठभेड़ के दौरान ग्रेनेड से दागे गए गोले से राज्य के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) का एक जवान घायल हो गया है। ज्वाइंट ऑपरेशन में डीआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और दूसरी यूनिट के जवान शामिल थे।

गुरुवार को शुरू हुआ था ऑपरेशन

गुरुवार को यह ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब खुफिया रिपोर्टों में बताया गया कि डीकेएसजेडसी सदस्य कमलेश और सीनियर कैडर नीती, नंदू और सुरेश सलाम सहित माओवादी नेता इलाके में छिपे हुए हैं। यह इलाके इंद्रावती क्षेत्र समिति, पीएलजीए कंपनी नंबर 6 और प्लाटून 16 जैसी माओवादी

यूनिट्स का गढ़ माना जाता है। अब तक 31 लोगों बरामद की गई हैं, तथा ऐसी खबरें हैं कि और भी माओवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने हथियारों का एक जखीरा भी जप्त किया, जिसमें एक एके-47, एक एसएलआर, एक इंसोस राइफल, एक एलएमजी और एके 303 राइफल शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुरक्षा बलों को बहादुरी की तारीफ की है और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। साल की शुरुआत से अब तक बस्तर इलाके में अलग-अलग ऑपरेशनों में 185 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे जिले शामिल हैं।

24.98 लाख से अधिक किसानों के खातों में पहुंचा 566 करोड़

-संवाददाता

उग्रत प्रवाह. रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले से देश के लगभग 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के रूप में 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम में वरुंचली शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 24 लाख 98 हजार से अधिक किसानों के खातों में 566 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र

वाले किसानों की संख्या 01 लाख 11 हजार 518 अधिक थी। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किरत-दर-किरत लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में बढ़ोतरी होना इस बात का प्रमाण है कि भारत के कृषि क्षेत्र में कितनी तेजी से प्रगति हो रही है। यह मोदी सरकार पर किसानों के मजबूत भरोसे का भी प्रमाण है। साय ने कहा कि 18 वीं किरत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई-



बहन आज लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें 02 लाख 49 हजार 867 वन-पड़ा धारक हैं और 30 हजार 408 किसान पीपीटीजी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों की उन्नति जय जवान-जय किसान के नारे को सार्थक कर रही है।

इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, कृषि मंत्री

रामविचार नेताम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टेकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, पुंरंद मिश्रा, ईश्वर साहू, गुरु खुरावंत साहब और डॉ. रामप्रताप मौजूद रहे।

किशन पटनायक होने का मतलब

-योगेन्द्र यादव

चुनाव परिणाम वाले दिन 'लल्लनटॉप' पर चल रही चर्चा को रोक कर अचानक सौरभ द्विवेदी ने मुझसे पूछा, 'आप अक्सर अपने गुरु किशन पटनायक की बात करते हैं। हमारे दर्शकों को उनके बारे में कुछ बताइए। मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। उस समय जो बन सका, कह दिया। लेकिन तब से यह सवाल लगातार मेरे भीतर चल रहा है- किशनजी का परिचय कैसे दूं? कोई साफ जवाब नहीं आता। लेकिन 27 सितंबर को उनकी बीसवीं बरसों पर एक कोशिश करना तो बनता है। किशन पटनायक (1930-2004) का सबसे आसान परिचय यह होगा कि वे एक राजनेता थे, समाजवादी नेता थे, पूर्व सांसद थे और वैकल्पिक राजनीति के सूत्रधार थे। वे युवावस्था में ही समाजवादी आंदोलन से जुड़े और महज 32 वर्ष की आयु में ओडिशा के संबलपुर से लोकसभा सदस्य चुने गये। समाजवादी आंदोलन के बिखराव के बाद उन्होंने लोहिया विचार मंच की स्थापना की, फिर 1980 में गैर-दलीय राजनीतिक औजार के रूप में समता संगठन बनाया और फिर 1995 में वैकल्पिक राजनीति के वाहन एक राजनीतिक दल 'समाजवादी जन परिषद' की स्थापना की।

जवानी में ही सांसद बनने के बाद भी उन्होंने जीवनभर कोई संपत्ति अर्जन नहीं किया, आर्थिक तंगी के बावजूद 60 साल की आयु तक पूर्व सांसद को पेंशन भी नहीं ली, दिल्ली में दूसरे सांसदों के सर्वेंट क्वार्टर में रहे, अपनी जीवनसंगिनी और स्कूल अध्यापिका वाणी मंजरी दास के वेतन में गुजारा किया, न परिवार का विस्तार किया, न ही बैंक बैलेंस रखा। राजनीति की दुनिया ने उन्हें ऐसे आदर्शवादी संत के रूप में देखा, जो मुख्यधारा की राजनीति में अस्फल हुआ। राजनीति की दुनिया अगर किशनजी की किसी सफलता को याद करेगी, तो एक गुरु के रूप में। बिहार में जेपी आंदोलन के समय से किशनजी के नेतृत्व में नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी और रघुपति जैसे अनेक युवा राजनीति में आये और कालांतर में मुख्यधारा की राजनीति से जुड़े। समता संगठन के जरिये रakesh सिन्हा, सुनील, स्वाति, सोमनाथ त्रिपाठी, जसबीर सिंह और विजय प्रताप जैसे आदर्शवादी राजनीतिक कार्यकर्ता उनके अभियान में जुड़े। देशभर में न जाने कितने राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकर्मी, बुद्धिजीवी, पत्रकार और लोक सेवक मिलते हैं, जिनके जीवन की दिशा किशनजी के संपर्क में आकर बदल गयी। उनमें इन पंक्तियों का लेखक भी शामिल है।

आज शायद देश उन्हें एक राजनीतिक चिंतक के रूप में याद करना चाहेगा। किशन पटनायक आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा की शायद अंतिम कड़ी थे। उनके चिंतन का प्रस्थान बिंदु बेशक लोहिया हैं, लेकिन उन्हें केवल लोहियावादी या समाजवादी चिंतक कहना सही नहीं होगा। बीसवीं सदी के भारत में राजनीतिक दर्शन की दो अलग-अलग धाराएं रही हैं- समतामूलक धारा और देशज विचार की धारा। किशन पटनायक इस दोनों धाराओं के बीच सेतु थे, जिन्होंने इन विचार परंपराओं को इकट्ठाकर सदी के लिए प्रासंगिक बनाया। राममनोहर लोहिया की पत्रिका 'मैनकाईड' के संपादन से शुरू कर किशनजी ने पहले 'चौरंगी वार्ता' और बाद में 'सामयिक वाता' पत्रिका का संपादन किया। उनके लेख अनेक पुस्तकों के रूप में संग्रहित हैं- 'विकल्प नहीं है दुनिया', 'भारत शूद्रों का होगा', 'किसान आंदोलन: दशा और दिशा और बदलाव की चुनौती। किशनजी ने समतामूलक वैचारिक परंपरा में पर्यावरण के सवाल और विस्थापन की चिंता के लिए जगह बनायी, हाशिये के इलाकों के मूलनिवासी की चिंता को समझा, जाति और आरक्षण के सवाल पर समाजवादी अग्रह को पैना किया, राष्ट्रवाद की सकारात्मक ऊर्जा को रेखांकित किया तथा लोहिया की वैचारिक परंपरा का गांधी और अंबेडकर की विरासत से संवाद स्थापित किया।

उन्हें जानने वाले किशनजी को एक असाधारण इंसान के रूप में याद रखेंगे, जो 'गीता' वाली स्थितप्रज्ञ की अवधारणा पर खरा उतरता था। सुख-दुख, सफलता-असफलता से निरपेक्ष। आत्मसल्लाघा से कोसों दूर। अपनी आलोचना सुनने और उससे सीखने का माद्दा। अपने लिए कम से कम जगह घेरने का अग्रह। सच्चाई उनके जीवन के हर पक्ष को परिभाषित करती थी। उनका संग संगी सायने में एक सतसंग था- सत्य का संग। नये लोगों को यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति भारत की राजनीति में बीस साल पहले तक मौजूद था। ये सब परिचय जरूरी हैं, लेकिन अधूरे हैं। चूंकि ये परिचय कुछ खांचों में बंधे हैं- नेता बनाम साधु, कार्यकर्ता बनाम चिंतक, सत्ता बनाम समाज। किशन पटनायक उस युग की याद दिलाते हैं, जिसमें एक राजनेता और चिंतक में फांक नहीं थी। राजनीति विचार से दिशा लेती थी और विचार राजनीति से गति पाते थे। किशनजी को याद करना हमारी सभ्यता में साधु की भूमिका को याद करना है, जिसका काम राजा को सच का आईना दिखाना था। किशनजी हमें उस मर्यादा की कौल की याद दिलाते हैं, जो हमारी नजर से ओझल रहती है, पर उसने सदियों से हमारी सभ्यता की चौखट को खड़ा रखा है। किशन पटनायक को याद करना उस भविष्य को जीवित रखना है, जहां राजनीति शुभ को सच में बदलने का कर्मयोग है।

सम्पादकीय

आखिर दो अच्छे दोस्त देशों में कैसे उत्पन्न हो गई दुश्मनी

इस समय ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है, दोनों देश आमने सामने हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए लगातार मिसाइली हमले कर रहे हैं। 27 सितंबर को इजराइली हमले में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत के बाद, ईरान ने इजराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके जवाब में, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सख्त चेतावनी कहा कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। इजरायल और ईरान के इस तनाव और दुश्मनी को देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि ये दोनों देश कभी दोस्त हुआ करते थे। हाँ, एक समय ऐसा था जब ईरान और इजराइल के बीच दोस्ताना संबंध हुआ करते थे। यह स्थिति 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति से पहले की है, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। 1950 के दशक से 1979 तक शाह के शासनकाल के दौरान, ईरान और इजराइल के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंध थे। दोनों देशों ने, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा और खुफिया जानकारी



के आदान-प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग किया। 1948 में एक ऐसा दौर भी आया जब ईरान ने इजरायल को मान्यता दी और इसके बाद 1968 में ईरान और इजरायल के बीच तेल पाइपलाइन शुरू हुई जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हुए। ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद, अयातुल्लाह खुमैनी ने सत्ता संभाली और इजराइल के साथ ईरान के संबंधों में भारी बदलाव आया। नई ईरानी सरकार ने इजराइल को "शैतान राज्य" घोषित किया और फिलिस्तीन के समर्थन में आ गई। इसके बाद, दोनों देशों के बीच सभी प्रकार के कूटनीतिक और आर्थिक संबंध समाप्त हो गए और शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया गया। जिसके बाद हमारा जैसे संडगनों का निर्माण हुआ और इजरायल पर हमले ने भी अपने खिलाफ उठ रही उन सभी आवाजों को खत्म किया जो इजरायल के लिए खतरा बन रही थीं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो, ईरान और इजराइल के बीच कभी बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद, वे शत्रु बन गए और आज स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण नजर आती है।

सियासी गहमागहमी

क्या सीबीआई के शिकंजे में होंगे बघेल?



पिछले पांच सालों में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भूपेश बघेल ने जो भी भ्रष्टाचार के कार्यों को अंजाम दिया है अब उनकी परते खुलना शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार महादेव सट्टा एप मामले में प्रमुख आरोपी रहे बघेल को सीबीआई की एक टीम कभी भी गिरफ्तार करने रायपुर पहुंच सकती है। बघेल को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा है शायद यही वजह है

कि वे लगातार कांग्रेस आलाकमान के आगे पीछे होकर खुद को राज्यसभा कोटे से संसद भवन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार बघेल के अलावा उनके करीबी लोगों पर भी एक बार फिर सीबीआई की एक टीम शिकंजा कस सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि बघेल सीबीआई के इस जाल से खुद को किस तरह से बचा पाते हैं।

बीजेपी सदस्यता अभियान का दौर है जारी



मध्यप्रदेश भाजपा की राजधानी भोपाल में इन दिनों बीजेपी सदस्यता अभियान का दौर जारी है। पहले तिरंगा यात्रा और सदस्यता लेकर नरेला विधानसभा में जबरदस्त दौरा जारी है। विश्वास सारंग मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से लगातार इस तरह के आयोजन करने में जुटे हैं।

चर्चा इस बात को लेकर भी है कि सारंग अपनी सीट पक्की करने जुटे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार आगामी मंत्रीमंडल में वर्तमान मंत्री विश्वास सारंग का पता काटे जाने की चर्चा है। ऐसे में भोपाल सीट से रामेश्वर शर्मा अपनी दायिदारी को तेज करने के लिये लगे हुए हैं।

हपते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

दलित विप्लव के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा शहू पटोले जी ने कहा, "दलित क्या खाते हैं, कोई नहीं जानता!"

ये क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, और इसका सांगठिक और राजनीतिक गहवर क्या है, इस जिज्ञासा के साथ, मैंने अजय तुकाराम सनदे जी और अंजना तुकाराम सनदे जी के साथ एक दोपहर बिताई।

-राहुल गांधी

कावेस गैता @RahulGandhi



मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ की इनस बरामद होना अरुच्य पिता का विषय है।

उससे भी बड़ी पिता की बात यह है कि राजधानी में चल रहे इस काले कारोबार का भंडाफेड़ करने में एमपी की जीप एजेंसियाँ नाकाम रही और दूसरे राज्य की पुलिस ने यह काम अंजाम दिया।

-कमलनाथ



प्रेम कावेस 88299

@OfficeOfRNath

राजवीरों की बात

अभिनेत्री से लोकसभा
सांसद तक का सफर तय
कर चुकी हैं कंगना

समता पाठक/जगत प्रवाह



बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत अब भाजपा से सांसद बन चुकी हैं। इन दिनों कंगना रनौत किसान आंदोलन पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, जिस पर उनकी पार्टी भाजपा ने भी उनकी इस टिप्पणी से किनारा कर लिया। दरअसल, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि आंदोलन के दौरान कई हत्याएं हुईं और बलात्कार हुए थे। उनके इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। जिसके बाद कंगना रनौत काफी चर्चा में हैं। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के भांबला में हुआ था। कंगना ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पढ़ाई की है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंगना रनौत ने 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई से ज्यादा उनकी दिलचस्पी मॉडलिंग में हो गई और उन्होंने मॉडलिंग में करियर बनाने की सोची। बाद में वह इसी दिशा में आगे बढ़ गईं। उन्होंने इसके आगे पढ़ाई नहीं की और मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया। इस तरह कंगना रनौत मॉडलिंग से होते हुए फिल्मों तक पहुंच गईं और उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह मंडी लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गईं।

कहा यह भी जाता है कि कंगना रनौत के माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी मेडिकल टेस्ट में सफलता नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की ट्रेनिंग की और दिल्ली आकर थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने मुंबई में गैंगस्टर के लिए ऑडिशन दिया लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में उन्हें दो महीने बाद उन्हें लीड रोल ऑफर किया गया। कंगना रनौत के परिवार में उनके पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन हैं, वहीं उनकी मां एक टीचर थीं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भाई अक्षत रनौत पहले पायलट थे, अब फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं। कंगना की भाभी व अक्षत की पत्नी त्रुत सांवान पेशे से डॉक्टर हैं। कंगना की बहन रंगोली कंगना की टीम का मैनेजमेंट देखती हैं।

नवरात्र में साधना से उत्पन्न होती उर्जा

आज की
बात
प्रवीण
कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

जगत प्रवाह. ओजाल।

अपनी नवरात्रि को अधिक शुभ एवं फलकारी बनाने के लिए जब आप नौ दिन तक निरंतर देवी माँ की साधना अर्थात् मंत्र-पाठ और जप-तप करते हैं तो आपकी सारी इन्द्रियां जागृत हो जाती हैं। इससे आपके भीतर स्फूर्ति का संचार होता है। इन नौ दिनों की साधना से मन के अंदर उर्जा और स्फूर्ति हमें प्रफुल्लित करती है। नवरात्रि को देवत्व के स्वर्ग से धरती पर उतरने का विशेष पर्व माना जाता है। उस अवसर पर सुसंस्कारी आत्माएँ अपने भीतर समुद्र मंथन जैसी हलचलें उभरती देखते हैं। जो उन्हें सुनियोजित कर सकें वे वैसी ही रत्न राशि उपलब्ध करते हैं जैसी कि पौराणिक काल में उपलब्ध हुईं मानी जाती हैं। इन दिनों परिष्कृत अन्तराल में ऐसी उमंगें भी उठती हैं जिनका अनुसरण सम्भव हो सके तो देवी अनुग्रह पाने का ही नहीं देवोपम बनने का अवसर भी मिलता है यों ईश्वरीय अनुग्रह सत्पात्रों पर सदा ही

बरसता है, पर ऐसे कुछ विशेष अवसर मिल सके। इन अवसरों को पावन पर्व कहते हैं। नवरात्रियों का पर्व मुहूर्तों में विशेष स्थान है।



उस अवसर पर देव प्रकृति की आत्माएँ किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित होकर आत्म कल्याण एवं लोक मंगल क्रिया कलाओं में अनायास ही

रस लेने लगती हैं। नवरात्रि देव पर्व है। उसमें देवत्व की प्रेरणा और उंची अनुकम्पा बरसती है। जो उस अवसर पर सक्तता बरतते और प्रयत्नरत होते हैं, वे अन्य अवसरों की उपेक्षा इस शुभ मुहूर्त का लाभ ही अधिक उठाते हैं। भौतिक लाभों को सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। संकटों के निवारण और प्रगति के अनुकूलन में सिद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। उस आधार पर जो मिलता है उसे वरदान कहा जाता है। नवरात्रियों वरदानों की अधिष्ठात्री कही जाती है, पर इस शुभ अवसर पर वास्तविक लाभ है देवत्व की विभूतियों का जीवनचर्या में समावेश। वह जिसे पितृनी मात्रा में मिलता है वह उतनी ही कला क्षमता का नर देव कहलाता है। देवता स्वर्ग में ही नहीं रहते अपितु महामानवों के रूप में इस धरती पर विचरते हैं। (जगत फीचर्स)

ॐ जयन्ती मंगला काली भद्र काली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते..!!

-सुनील कुमार

भक्ति और शक्ति को उपासना का पवित्र महापर्व नव दुर्गा पूजा, जिसे नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र त्योहारों में से एक है। इस पर्व की शुरुआत प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का पवित्र महापर्व 3 अक्टूबर 2024 (बृहस्पतिवार) से शुरू होकर 11 अक्टूबर 2024 (शुक्रवार) को समाप्त होगा तथा 12 अक्टूबर 24 (शनिवार) को दुर्गा विसर्जन होगा। यह पर्व नौ दिनों तक देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा और साधना को समर्पित होता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने अश्विन माह में दुर्दांत शक्तिशाली राक्षस महिषासुर से 09 दिनों तक युद्ध कर नवमी की रात्रि को उसका वध किया था, इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए अर्पित कर दिया गया। नौ दिनों तक चलने वाले इस पवित्र पर्व में हर दिन माँ भगवती दुर्गा जिन्हें आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है के अलग-अलग रूपों में से एक-एक रूप की पूजा व साधना की जाती है तथा विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है।

नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ "नौ रातें" होता है, और इन दिनों में भक्त उपवास रखकर शक्ति स्वरूपा माँ देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना कर मातारानी की कृपा प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। भक्त घरों और मंदिरों में माँ दुर्गा के नाम से भजन-कीर्तन करते हैं। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें नौ कन्याओं को देवी का रूप मानकर

उनका पूजन किया जाता है। माँ भगवती नवदुर्गा के नौ रूप—शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कृष्णान्दा, स्कंदमाता, काल्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, और सिद्धिदात्री—प्रकृति के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर देवी के अलग-अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं परन्तु यह सब एक हैं और सभी परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं जिन्हें पापों की विनाशिनी कहा जाता है। इन नौ दिनों में प्रत्येक दिन माँ देवी दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा व साधना की जाती है। यह पूजा देवी के विभिन्न स्वरूपों के गुणों और उनकी शक्तियों को समझने और उनके प्रति आस्था, भक्ति व सम्मान प्रकट करने का एक माध्यम है :-

1. शैलपुत्री: यह देवी का पहला रूप है। देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इन्हें प्रकृति की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह नारी शक्ति का प्रतीक है।
2. ब्रह्मचारिणी: दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है, जो तपस्या और संयम की देवी हैं। उनकी पूजा से साधकों को आत्मबल और धैर्य की प्राप्ति होती है।
3. चंद्रघंटा: तीसरा रूप चंद्रघंटा का है, जो शांति और वीरता का प्रतीक है। इनके माथे पर अर्धचंद्र है और यह अपने भक्तों को साहस और शांति का आशीर्वाद देती हैं।
4. कृष्णान्दा: चौथा रूप देवी कृष्णान्दा का है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। यह देवी ऊर्जा और शक्ति की देवी हैं, जो अपने भक्तों को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं।
5. स्कंदमाता: पाँचवाँ रूप स्कंदमाता का है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। यह मातृत्व

और स्नेह का प्रतीक मानी जाती हैं और संतान की मंगलकामना के लिए पूजा जाता है।

6. काल्यायनी: छठा रूप काल्यायनी का है, जो महर्षि काल्यायन की पुत्री हैं। यह युद्ध और विजय की देवी मानी जाती हैं और उनके भक्तों को साहस और वीरता प्राप्त होती है।

7. कालरात्रि: सातवाँ रूप कालरात्रि का है, जो काले रंग की देवी हैं और सभी दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं। यह रूप अज्ञान और अंधकार को समाप्त करता है और जीवन में प्रकाश लाता है।

8. महागौरी: आठवाँ रूप महागौरी का है, जो अत्यंत श्वेत वर्ण की हैं और पवित्रता की प्रतीक मानी जाती हैं। इनके पूजन से भक्तों को सुख-समृद्धि और शांति मिलती है।

9. सिद्धिदात्री: नवम और अंतिम रूप सिद्धिदात्री का है, जो सभी सिद्धियों की देवी हैं। यह भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान की प्राप्ति कराती हैं।

नवदुर्गा पूजा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें समाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी शामिल हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। पश्चिमी भारत में गरबा और डाँडिया जैसी नृत्य प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, जबकि पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। भक्त देवी की विशाल मूर्तियों को स्थापना करते हैं, और इन नौ दिनों के बाद, दशहरे के दिन देवी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

(लेखक, पुरिष आध्यात्मिकीकार, गद्य वेध, सीआरपीएफ, लखनऊ)

संयुक्त राष्ट्र में भारत का भारी होता पलड़ा



-प्रमोद भार्गव

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र निकाय के विस्तार की वकालत की है। मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में

कहा कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही दो ऐसे देश भी होने चाहिए, जिन्हें अफ्रीका प्रतिनिधित्व के लिए अनुशंसा करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान से दोस्ती और भारत विरोधी रुख के लिए चर्चित तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को इटका दिया है। उन्होंने गाजा युद्ध को लेकर जमकर हमला बोला, लेकिन इस बार कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। साल 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर किनारा किया है। इससे पहले उन्होंने साल 2020, 2021, 2022 और 2023 में कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया था। इससे लगता है कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सहमति बढ़ रही है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक प्रभाव और सफल कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

भारत के संयुक्त राष्ट्र में भारी होते पलड़े के संदर्भ में विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्किये ब्रिक्स का सदस्य देश बनना चाहता है। इस हेतु उसे भारत की मदद जरूरी है। यदि भारत असहमति जता देता है तो उसे सदस्यता मिलना मुश्किल है। ब्रिक्स में इस वक्त चाइनीज, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। भारत इसमें प्रमुख सदस्यों में से एक है। इस बीच खबर यह भी है कि तुर्किये को नतीजा देशों के समूह से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए तुर्किये ब्रिक्स देशों की सदस्यता चाहता है। एर्दोगान ने कहा भी है कि 'हम ब्रिक्स देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहते हैं। ब्रिक्स के देश दुनिया की उभरती आर्थिक शक्ति है। इसलिए हम उनके साथ संबंध मजबूत और विश्वसनीय बनाने के पक्षधर हैं।' एर्दोगान ने यह इटका तब दिया है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि महासभा में कश्मीर में हो रहे चुनाव का मुद्दा उठाया जाए और इस चुनाव प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक बताया जाए। परंतु दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे भारत का डंका विष्व की अन्य अलोकतांत्रिक और मानवाधिकार हितों की पैरवी करने वाली संस्थाओं में बजला दिख रहा है।

इस परिप्रेक्ष्य में भारत की दलील है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की लक्ष्य पूर्तियों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य देश

शामिल हैं। जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। परंतु पांच स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं, इनमें से प्रत्येक देश के पास ऐसी शक्ति है, जो किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वीटो लगा सकता है। भारत 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र की उच्च परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। किंतु दुनिया का जो वर्तमान परिदृश्य है, उससे निपटने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या दुनिया का हित साधने के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। इसीलिए मैक्रों को कहना पड़ा कि 'सुरक्षा परिषद के काम काज के तरीकों में बदलाव, सामूहिक अपराधों के मामलों में वीटो के अधिकार को सीमित करने और शक्ति बनाए रखने के लिए जरूरी फैसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। अतएव जमीन पर बेहतर और

बेहतर तरीके से काम करने की दृष्टि से दक्षता हासिल करने का समय आ गया है। मैक्रों की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बीते रविवार 22 सितंबर 2024 को 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' को संबोधित करने के कुछ दिन बाद आई है, इसमें मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि वैश्विक शांति और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है।' वाकई इस समय संस्थाएं अपनी प्रासंगिकता खोती दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेर्रेस ने 15 सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद को भी पुरानी व्यवस्था का हिस्सा बताकर आलोचना की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर इसकी संरचना और कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो इस संस्था से दुनिया का भरोसा उठ जाएगा।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांतिप्रिय देशों के संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था। इसका अहम मकसद भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका और आतंकवाद से सुरक्षित रखना था। इसके सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को स्थायी सदस्यता प्राप्त है। याद रहे चीन जवाहरलाल नेहरू की अनुकंपा से सुरक्षा परिषद का सदस्य बना था। कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव रहे शशि थरुन की किताब 'नेहरू-ड इन्वेन्शंस ऑफ इंडिया' में थरुन ने लिखा है कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था। लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। थरुन ने लिखा है कि भारतीय राजनयिकों ने वह फाइल देखी थी, जिस पर नेहरू के इंकार का जिक्र है। नेहरू ने ताइवान के बाद इस सदस्यता को चीन को देने की पैरवी की थी। अतएव कहा जा सकता है कि नेहरू की भयंकर भूल और उदारता का नुकसान भारत आज तक उठा रहा है। जबकि उस समय अमेरिका भारत के पक्ष में था।

भारत का दो बार पाकिस्तान और एक बार चीन से युद्ध हो चुका है। इराक और अफगानिस्तान, अमेरिका और रूस के जबरन दखल के चलते युद्ध की ऐसी विभीषिका के शिकार हुए कि आज तक उबर नहीं पाए हैं। तालिबान की आमद के बाद अफगानिस्तान में किस बेरहमी से विरोधियों और स्त्रियों को दंडित किया जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं रह गया है? इजराइल और फिलीस्तीन और रूस एवं अमेरिका के बीच युद्ध एक नहीं टूटने वाली कड़ी बन गए हैं। अनेक इस्लामिक देश गृह-न्तलह से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। दुनिया में फैल चुके इस्लामिक आतंकवाद पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा चीन किसी वैश्विक पंचायत के



सुरक्षा परिषद में सुधार से बढ़ेगी संयुक्त राष्ट्र की हैसियत

संयुक्त राष्ट्र की लचर एवं पक्षपाती भूमिका के चलते उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब तो यह लगने लगा है कि यदि सुरक्षा परिषद जल्द सुधार नहीं किए गए तो संयुक्त राष्ट्र का वर्चस्व महत्वहीन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में परिषद के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक दुनिया बड़े परिवर्तनों की वाहक बन चुकी है। इसीलिए भारत लंबे समय से परिषद के पुनर्गठन का प्रश्न परिषद की बैठकों में उठा रहा है। कालांतर में इसका प्रभाव यह पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देश भी इस प्रश्न की कड़ी के साझेदार बनते चले गए। जी-4 देश ब्राजील, भारत, जर्मनी और जापान निरंतर इस मांग को उठा रहे हैं। परिषद के स्थायी व वीटोधारी देशों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भी अपना मौखिक समर्थन इस प्रश्न के पक्ष में देते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से दो तिहाई से भी अधिक देशों ने सुधार और विस्तार के लिखित प्रस्ताव को मंजूरी 2015 में दे दी थी। इस मंजूरी के चलते अब यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे का अहम मुद्दा बन गया है। नतीजतन अब यह मसला एक तो परिषद में सुधार की मांग करने वाले भारत जैसे चंद देशों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि महासभा के सदस्य देशों की सामूहिक कार्यसूची का प्रश्न बन गया है। यदि पुनर्गठन होता है तो सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व को समतामूलक बनाए जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। परिषद में अभी पश्चिम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अतएव सुधार प्रक्रिया जाता है तो इन देशों की भूमिका भी रेखांकित होगी।

निर्विवाद एवं समतामूलक वैश्विक लक्ष्य साधने हैं तो परिषद में नए स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ानी अनिवार्य है। यह संख्या बढ़ती है तो परिषद की असमता दूर होने के साथ इसकी कार्य-संस्कृति में लोकतांत्रिक संभावनाएं स्वतः बढ़ जाएगी। परिषद की महासभा में इन प्रस्तावों का शामिल होना, बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि तो थी, लेकिन परिणाम भारत और इसमें बदलाव को अपेक्षा रखने वाले देशों के पक्ष में आगे हो, इसमें शंका प्रकट है। असमानता दूर करने के लिए उचित प्रतिनिधित्व हेतु सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से जुड़े मामलों पर लंबी चर्चा होगी। सभा में बहुमत से पारित होने वाली समितियों के आधार पर 'अंतिम अभिलेख' की रूपरेखा तैयार होगी। किंतु यह जरूरी नहीं कि यह अभिलेख किसी देश की इच्छाओं के अनुरूप ही हो? क्योंकि इसमें बहुमत से लाए गए प्रस्तावों को खारिज करने का अधिकार पी-5 देशों को है। ये देश किसी प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं तो यथास्थिति और टकराव बरकरार रहेंगे। साथ ही यदि किसी नए देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल भी जाती है तो यह प्रश्न भी कथम रहेगा कि उन्हें वीटो की शक्ति दी जाती है अथवा नहीं? हालांकि भारत कई दृष्टियों से न केवल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की हैसियत रखता है, बल्कि वीटो-शक्ति हासिल कर लेने की पात्रता भी उसमें है। क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ और शांति सेना जैसे संगठन काम करते हैं। क्योंकि स्थायी सदस्य देशों ने इन्हें हाईजैक किया हुआ है। अतएव इन देशों की ताकत के आगे ये संगठन नतमस्तक होते दिखाई देते हैं।

आदेश को नहीं मानता। इसका उदाहरण अजहर जैसे आतंकीयों को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर चीन का बार-बार वीटो का इस्तेमाल करना है। जबकि भारत विश्व में शांति स्थापित करने के अभियानों में मुख्य भूमिका निवाह करता रहा है। बावजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी एवं सामुदायिक बहुलता वाला देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। भारत में दुनिया की 18 पैसेवदी आबादी रहती है। दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। साफ है, संयुक्त राष्ट्र की कार्य-संस्कृति निष्पक्ष नहीं है। कोरोना महामारी के दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानवावादी केंद्रीय भूमिका दिखनी चाहिए थी, लेकिन वह मरामापी फैलाने वाले दोषी देश चीन के समर्थन में खड़ा नजर आया। अलबत्ता सुरक्षा परिषद की भूमिका वैश्विक संगठन होने की दृष्टि से इसलिए अधिक प्रतीति मानी जाती है, क्योंकि उसके अजेंडे में प्रतिबंध लागू करने और संघर्ष की स्थिति में सैनिक कार्रवाई की अनुमति देने के अधिकार शामिल हैं। इस नतीजे से विश्वका का संकट पद्धति में शक्ति-संतुलन बनाए रखने की भावना अंतर्निहित है। लेकिन वह इन प्रतिबद्धताओं को नजरअंदाज कर रहा है, गोपा संस्था के प्रति विश्वास का संकट गहराया हुआ है। नतीजतन इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है राज्य को नक्सल समस्या मुक्त बनाने का संकल्प

(पेज 1 का शेष)

जानकारों की मानें तो पूर्ववर्ती कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार के समय में नक्सलवाद बेहद तेजी से बढ़ा और राज्य में नक्सलियों ने आतंक मचा दिया था।

36 नक्सलियों को मार गिराकर जाहिर की प्रतिबद्धता

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई में करीब 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इस नक्सल विरोधी ऑपरेशन को छत्तीसगढ़ के देतेवाड़ा-नाराजयणपुर जिले की सीमा से लगे अब्दुलमादक के जंगलों में सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया। यह इस साल के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में से एक है। हालांकि इस ऑपरेशन की जमीन काफी पहले से तैयार की जा रही थी। इसका संकेत सरकार ने पहले ही दे दिया था।

मांरी मात्रा में हथियार बरामद

पुलिस के मुताबिक मौके से 1 AK-47 और 1 SLR समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। इस साल में अबतक छत्तीसगढ़ के अलग-अलग इलाकों से मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 185 से अधिक नक्सलियों का सफाया कर दिया है। बीते महीने देतेवाड़ा की पुलिस ने 8 नक्सलियों को डेर कर दिया था।

2026 तक नक्सलमुक्त करने का दावा

केंद्र सरकार ने 2026 तक माओवादियों के सफाए के लिए रणनीति बनाई है। नक्सलियों से लड़ने के लिए इस इलाकों फोर्स को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने दावा करते हुए कहा कि 2026 तक नक्सलमुक्त होने के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग

जानकारी के अनुसार इलाके में अभी भी रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपने आवास पर पुलिस विभाग के सीनियर ऑफिसर्स की हाई लेवल मीटिंग बुलाई और नाराजयणपुर-देतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षाबल के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने पर पुलिसबल के जवानों को मिली सफलता के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, 'जवानों को मिली यह बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को मैं नमन करता हूँ। नक्सलवाद के खत्म के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंच रही हम लेंगे, इसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश से नक्सलवाद का खतमा ही हमारा लक्ष्य है। नक्सलवाद के खत्म तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी।

09 महीने में दो बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं केंद्रीय गृहमंत्री

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विगत 09 महीने में नक्सलवाद की समीक्षा हेतु दो बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए। उनकी सोच के अनुरूप हमारे जवान छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवादियों से मुकाबला कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में खाकी वर्दी वाले संरक्षक बनते जा रहे भक्षक

(पेज 1 का शेष)

लाठी चार्ज करने के लगे आरोप

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने वाले अतिथि शिक्षकों पर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर भोपाल में रात के समय बिजली बंद करके लाठीचार्ज करने का आरोप लगे थे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाईकोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उच्च न्यायालय में जमानत पत्र दाखिल करके आगे अतिथि शिक्षकों के साथ की गई बर्बरता की जो खबरें सामने आ रही हैं, यह बहुत चौंकाने वाली है और यह दिखाती है कि प्रदेश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति पूरी तरह चौपट है।

एक-एक लाठी अत्याचार की ड़बारत

कमलनाथ ने सोशल साइट एकस पर लिखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले अतिथि शिक्षकों पर रात के

अंधेरे में बिजली गुल करके किया गया लाठीचार्ज लोकतंत्र के माथे पर धक्का है। अतिथि शिक्षकों के शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी डॉक्टर मोहन यादव सरकार के अत्याचार की इबारत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मध्यप्रदेश में अपनी जायज मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गुनाह हो गया है? नाथ ने लिखा है कि मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि अतिथि शिक्षकों के साथ हुए अत्याचार की हाई कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो भी इसके लिए दोषी पाए जाते हैं, उन्हें कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए।

स्कूल शिक्षा मंत्री के गलत बयान ने दिया मामले को तूल

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के एक बयान के बाद यह मामला और गरमा गया था। वहीं अब अपने ही बयान पर मंत्री ने खेद व्यक्त किया है। लेकिन कांग्रेस मंत्री को लेकर हमलावर है। कांग्रेस ने प्रदेश में मंत्री के बयान को लेकर प्रदर्शन की तैयारी कर दी है। क्योंकि कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों का समर्थन किया था। लेकिन मंत्री ने अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। नरसिंहपुर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा 'अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश के और हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं, उनके

विषय में हम सोच रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अगर मेरी किसी बात का अतिथि शिक्षकों को ठेस पहुंची बुरा लगा है तो मैं उस बात के लिए खेद व्यक्त करता हूँ। सरकार लगातार अतिथि शिक्षकों को लेकर समीक्षा कर रही है। मंत्री ने पिछले दिनों अतिथि शिक्षकों की नियमितिकरण को लेकर कहा था कि मेहमान बनकर आए थे क्या घर में कब्जा कर लेंगे।

अतिथि शिक्षकों ने किया विरोध

दरअसल, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनमें नियमितिकरण की मांग भी शामिल है। 10 सितंबर के दिन भी भोपाल में 8 हजार अतिथि शिक्षकों ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की थी। जिसके बाद मंत्रियों ने अतिथि शिक्षकों से मुलाकात कर कुछ मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितिकरण की मांग कर रहे हैं। मंत्री के उदय प्रताप सिंह के बयान के बाद यह मामला और गड़बड़ा गया था। जिसके बाद अतिथि शिक्षकों ने मंत्री के बयान का विरोध भी किया था।

अधर में है अतिथि शिक्षकों का भविष्य

मध्यप्रदेश के स्कूलों में बीते 18 वर्ष से काम कर रहे अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितिकरण की मांग कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि

सरकार ने अतिशय शिक्षकों की भर्ती का दांव खेलकर उन्हें सड़कों पर आने मजबूर कर दिया है। प्रदेश में करीब 35 हजार अतिशय शिक्षकों की सूची आने के बाद अब अतिथि शिक्षकों का मामला फिर लटकता दिखाई दे रहा है। इस सूची के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति फिर अटक गई है। हालांकि इन शिक्षकों को अगस्त महीने से ही स्कूलों में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाना था लेकिन अब ये खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है।

परफार्मेंस के आधार पर बाहर हो चुके हैं कई अतिथि शिक्षक

अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि अतिशय शिक्षकों की वजह से 80 फीसदी से ज्यादा शिक्षक इसी सत्र में बेरोजगार हो जाएंगे। असल में 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम अच्छा नहीं आने के बाद तय था कि अगस्त से अतिथि शिक्षक कक्षाएं लेंगे लेकिन रिक्त पदों में ना अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई ना उन्हें पढ़ाने आमंत्रित किये जाने पर भी रोक लगा दी गई। ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी बोर्ड परीक्षाओं में परफार्मेंस के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने ये कट दिया था कि 30 फीसदी के नीचे अगर रिजल्ट आया तो उन अतिथि शिक्षकों को फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। 12 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षक इसी में बाहर हो गए।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कांग्रेस पार्टी की एकता और विश्वसनीयता से उठाया पर्दा

(पेज 1 का शेष)

उमंग सिंगार के इस कदम ने जीतू पटवारी और उनके बीच के तालमेल पर सवाल खड़ा कर दिया है। चर्चा इस बात की भी है कि सिंगार लगातार कांग्रेस विधायकों को पटवारी के खिलाफ उकसाने में जुटे हैं और पिछले दिनों पटवारी की शिकायत भी आलाकमान से करवाने की साजिश भी सिंगार के इशारे पर ही रची गई थी।

अखिर कहां चली गई कांग्रेस नेताओं की एकता

एक समय था जब कांग्रेस नेता और पार्टी आपसी एकता और समन्वय के लिए पूरे देश ने खास पहचान रखती थी। लेकिन उमंग सिंगार के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पार्टी नेताओं में अंदर ही अंदर मनभेद पनप रहा है जो मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में साफ दिखाई भी दिया। पार्टी के 67 विधायक होने के बाद भी महज 38 विधायक ही मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। पार्टी विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सिंगार ने अपने गुट के ही विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलने की सूचना दी थी। बाकी अन्य विधायकों के इस बारे में चर्चा भी नहीं की।

सिंगार की इस साजिश ने पार्टी की एकता पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया था। माना जा सकता है कि जो विधायक उमंग सिंगार के साथ गये हैं वह तो सिंगार के गुट के हो सकते हैं तो बाकी विधायक किस गुट के हैं। यह भी बड़ा सवाल है।

अखिर ऐसे कैसे प्रदेश में मजबूत होगी कांग्रेस

उमंग सिंगार के इस कदम ने पार्टी की छवि तो धूमिल की ही है साथ ही उन्होंने पार्टी के नियमों का भी उल्लंघन किया है। चर्चा इस बात की है कि जैसे ही पार्टी नेताओं की मुख्यमंत्री से मुलाकात की जानकारी सार्वजनिक हुई पार्टी आलाकमान खासा नाराज हुआ और उन्होंने तुरंत पटवारी सहित सिंगार के बीच पनप रही गुटबाजी की राजनीति को यही समाप्त करने का आदेश दिया। जाहिर है कि पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा उठाया गया यह कदम कहीं न कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपसी वैमनस्य का यह दौर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पार्टी मध्यप्रदेश में खत्म हो जाएगी और पार्टी को आगामी विधानसभा और

लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना बड़ी मुश्किल की बात होगी।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय कमी ऐसा नहीं हुआ

प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई नेता अपना समर्थकों के साथ बैंगर प्रदेश अध्यक्ष के बिना मुख्यमंत्री से मिला हो। वह चाहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हों। इन दोनों के कार्यकाल में इस तरह की अनुरासनहीनता नहीं होती थी। सभी विधायक एकजुट होकर सरकार के पास जाते थे और जो भी बात होती थी वह प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से ही होती थी। यही पार्टी की लाईन है। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच इस तरह का मनमुटवय पहले कभी भी नहीं देखा गया है। जैसे भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का अनुरासनहीनता यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वह अपने सांनिध्य नेताओं का मंच से अपमान करते रहे हैं। अपने बड़बोलपन में वह सारी मर्यादाएं भूल जाते हैं। अब जब वह नेता प्रतिपक्ष हैं तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही अन्य

नेताओं के साथ भी उमंग सिंगार का व्यवहार अच्छा नहीं है।

मुख्यमंत्री ने भी नहीं दी तवज्जो

बगैर प्रदेश अध्यक्ष व अधिक संख्या वाले विधान मिलने पहुंचे विधायकों को मुख्यमंत्री डॉ. माहन यादव ने भी तवज्जो नहीं दी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक की समस्याओं को सुना और कहा कि मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक विषय प्रदेश के लिए भी बेहतर काम करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी विधायकों से चर्चा की है। खासकर पहले हमने अपनी फसलों के सर्वे का फैसला किया। जिसके लिए हमने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका निराकरण करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी विधायक वो चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के सभी अपनी-अपनी विधानसभाओं में विजन डोक्यूमेंट बनाएं। पांच सालों में विकास के मामले में वो अपनी विधानसभा को कहां ले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे।



विष्णु के सुशासन से
सीवर रह छत्तीसगढ़



श्री नरेन्द्र मोदी
राष्ट्रपति, प्रजासत्ताक



श्री विष्णु देव साstry
सुपरी, छत्तीसगढ़

सुशासन से विकास की नई राह...

- कुल 10000 करोड़ : राज का बड़े विविध 1000 करोड़ मिल रहा है, लोहा-चिनासी से खुले बाजार के द्वार
- सुदूरगंगा-अरावली राजमार्ग (बाजरा) - 47 हजार 500 अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य परिसरों को मिलेगा लाभ

- राष्ट्रीय स्तरों में प्रमुख क्षेत्रों में हुए, कुलित विकास लक्षित राष्ट्रीय स्तरों में प्रजाती को अधिकतर बाह्य क्षेत्रों में 5 करोड़ की पूरा
- बराबर हुए वाणिज्य स्तरों प्रकृत सुविधा



- सुदूर अरावली: राष्ट्रीय स्तरों के 50 लाख वर्ग मीटरों को अरावली क्षेत्र राज्य को मिलेगा लाभ
- विदुषा राजमार्ग परियोजना: 1000 करोड़ से अधिक 5000 करोड़ तक लागत को

- "विश्व अंतरराष्ट्रीय" अर्थव्यवस्था के लाभ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के कुल विकास के स्तरों को
- अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था: विष्णु देव साstry में 100 करोड़ तक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में 10, 500 करोड़ मिलेगा, 100 करोड़ विकास अंतरराष्ट्रीय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साstry से जुड़ने के लिए यह क्विज कोड स्कैन करें...
हमने बनाया है, हम ही सँतारेंगे

